

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2013/भाद्र 5, 1935

[ग.रा.रा.क्षे.दि. सं. 110

No. 135]

DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2013/BHADRA 5, 1935

| N.C.T.D. No. 110

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूनाएं

दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

सं. 21 (06)/2013/एल ए एस-IV/एलईजी./5007.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या (06) 2013

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पुरःस्थापित किया गया)

2013 का विधेयक संख्या 06

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में पुनः संशोधन करने हेतु

एक

विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निमानुसार अधिनियमित किया जायेगा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।

2. धारा 2 का संशोधन—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3), इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” रूप में संदर्भित की धारा 2 की उप-धारा (1)।

(i) के खंड (ङ), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(ङ) “व्यापार परिसर” सम्मिलित है—

(i) व्यापारी का पता, आयुक्त के साथ पंजीकृत;

(ii) मूलतः आवास के रूप में उपयोग किये जा रहे भवन अथवा स्थल के उन भागों को छोड़कर, अपने व्यापार के संचालन के लिये किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग कोई भवन या स्थल;

(iii) किसी एजेंट के माध्यम से कोई व्यापारी किसी स्थान पर अपना व्यापार चलाता है (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो), ऐसे एजेंट के व्यापार का स्थल, तथा कोई भंडार गृह, गोदाम अथवा ऐसा अन्य स्थल जहाँ व्यापारी अपनी वस्तुओं का भंडारण करता है।”

(ii) खंड (एम) के उप-खंड (ii) में “चल” शब्द के पश्चात् “या अचल” शब्दों को सम्बन्धित किया जायेगा।

3. धारा 11 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(2) “जहाँ इस धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत व्यापारी को परिकलित शुद्ध कर की राशि शून्य है तो, व्यापारी—

(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अन्तर्गत उसके द्वारा देय कर के लिए उसी कर अवधि में उक्त राशि का समायोजन किया जाएगा, यदि कोई है; तथा

(ख) उसी वर्ष के अगले कैलेण्डर माह या कर अवधि के लिए, जैसी भी स्थिति हो, उप-धारा (2) के अन्तर्गत आवेदन के पश्चात् शेष राशि को अग्रेषित करने का पात्र होगा, अथवा

उसी वर्ष की कर अवधि के अन्त पर उप-धारा (2) (क) के अन्तर्गत आवेदन के पश्चात् शेष राशि के रिफंड का दावा करेगा तथा आयुक्त इस अधिनियम की धारा 38 तथा धारा 39 के अन्तर्गत वर्णित तरीके से धन वापसी पर कार्यवाही करेगा।

व्याख्या : 1. केवल कर अवधि के अन्त पर ही रिफंड का दावा किया जा सकेगा।

2. अधिक कर क्रेडिट आगामी वर्ष में अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

3. पूर्व वर्षों से अग्रेषित किया गया अधिक कर क्रेडिट का रिफंड वर्ष 2013-14 की किसी शेष कर अवधि में दावा किया जाएगा लेकिन 31-3-2014 को समाप्त अन्तिम कर अवधि के पश्चात् नहीं।

4. कर अवधि के अन्त पर शेष अधिक कर क्रेडिट या तो रिफंड के रूप में दावा अथवा उसी वर्ष की कर अवधि में अग्रेषित होगा।

5. अनजाने में किया गया अधिक भुगतान माह में अथवा कर अवधि, जैसी भी स्थिति हो, में क्रेडिट समझा जाएगा।”।

4. धारा 25 का संशोधन—मूल नियमावली की धारा 25 की उप-धारा (1) में “इस अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत” शब्दों के पश्चात् तथा “व्यक्ति के लिये अपेक्षित” शब्दों से पूर्व निम्नलिखित को सम्बन्धित किया जायेगा, अर्थात् :-

“धारा 60 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अथवा डी-सिलिंग या छोड़ने की शर्त के रूप में”

5. धारा 35 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(2) “जहाँ इस अधिनियम की धारा 74 में उपर्युक्त पद्धति से ऐसी आपत्ति को स्वीकार करने के लिए किसी कर निर्धारण या कर निर्धारण के भाग के लिए किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति की है और शर्त का पालन किया है, यदि कोई हो, तो आयुक्त, आयुक्त द्वारा आपत्ति के समाधान होने तक कर निर्धारण के अन्तर्गत विवादित शेष राशि के भुगतान को लागू नहीं कर सकता।”

6. धारा 48 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1) “प्रत्येक

(क) व्यापारी;

(ख) वह व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत रिटर्न भरने के लिए नोटिस तामील किया गया है;

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की राशि का तत्काल पता लगाने के लिए और समस्त सौदों, विषयों को स्पष्ट करने के लिए और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अन्य कृत्यों के लिए जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं को स्पष्ट करने के लिए आयुक्त को अनुमति करने के लिये वह अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज प्रमुख व्यापार स्थल पर पर्याप्त अभिलेख तैयार रखारखाव तथा परीक्षण करेगा :

बशर्ते कि व्यापारी कम्प्यूटरीकृत लेखा बहियों को रखेगा जिसमें साप्टवेयर जल्दी उपलब्ध होगा तथा/अथवा अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र अभिलेखबद्ध किया था, आयुक्त द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा ।

व्याख्या :-—इस उप-धारा की आवश्यकतानुसार व्यापारी अनुपालन के लिए अभिलेख की सॉफ्ट कॉपी को रखेगा ।"

7. धारा 58क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 58क, की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1) "यदि आयुक्त, का इस संबंध में--

- (क) व्यापारी के व्यवसाय की प्रकृति एवं जटिलता; अथवा
- (ख) राजस्व का व्याज; अथवा
- (ग) लेखा बहियों की मात्रा; अथवा
- (घ) लेखों की सत्यता के बारे में सन्देह; अथवा
- (ङ) लेखा बहियों में सौदों की बहुलता; अथवा
- (च) व्यापार गतिविधियों की विशेष प्रकृति; अथवा
- (छ) समस्त अभिलेखों एवं लेखा बहियों को प्रस्तुत न करना; अथवा
- (ज) इस अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा नहीं करना; अथवा
- (झ) अन्य कोई कारण ।

अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह व्यापारी को अपने अभिलेख जिसमें लेखा बहियां भी शामिल हैं, इस संबंध में आयुक्त द्वारा नामित किसी लेखाकार या लेखाकार के किसी पैनल या किसी अन्य व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल द्वारा जाँच तथा लेखा परीक्षा कराने के लिए लिखित में नोटिस देकर व्यापारी को निर्देश दे सकते हैं और ऐसी जाँच तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह ऐसे लेखाकार या लेखाकारों के पैनल या व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर और सत्यापित करने का उल्लेख कर सकता है और यथाविनिर्दिष्ट ऐसे विवरण का उल्लेख कर सकता है ।"

8. धारा 60 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (4) में "निदेशित" शब्द के स्थान पर "निर्धारित" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

9. धारा 70 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (5) को हटाया जायेगा ।

10. धारा 86 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 86 में--

(i) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1) इस धारा में "कर कमी" का अर्थ किसी कैलेंडर माह के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति द्वारा उचित रीति से देय कर की राशि तथा व्यक्ति द्वारा भुगतान किये गए कर की राशि के बीच अन्तर से है ।

व्याख्या 1 :-"उचित रीति से देय कर" में "अधिनियम" की धारा 32 के अन्तर्गत निर्धारित की गई कर की राशि शामिल है ।

2. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भुगतान किए गए देय कर की राशि भी कर कमी है ।"

(ii) उप-धारा (2) का द्वितीय उपबंध हटाया जाएगा ।

(iii) उप-धारा (5) में आए शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "पांच" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "दस" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(iv) उप-धारा (6) में आए शब्द "सौ" के स्थान पर शब्द "हजार" तथा शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "पचीस" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(v) उप-धारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(9) "यदि किसी व्यक्ति को अध्याय 5 के अन्तर्गत विवरणी प्रस्तुत करनी या इस अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना की अपेक्षा का अनुपालन करना अपेक्षित है तो—

- (क) देय तिथि तक कोई विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा
- (ख) किसी विवरणी के साथ कोई अन्य प्रलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है जो विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;
- (अ) पहले ही प्रस्तुत की गई विवरणी को संशोधित करना अपेक्षित होने पर देय तिथि तक संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा
- (घ) धारा 70 के अन्तर्गत जारी किसी अधिसूचना की अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहता है;
- तो व्यक्ति अर्थदंड के रूप में पांच सौ रुपये प्रतिदिन की दर से देय तिथि के तुरन्त बाद के दिन से लेकर विफलता का निवारण होने तक राशि के भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा :
- शर्त यह है कि इस उप-धारा के अन्तर्गत देय दंड की राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।”
- (vi) उप-धारा (13) के उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- (ग) निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख या लेखा रखना;

तथा व्यक्ति--

- (i) निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख तथा लेखा तैयार करने में विफल रहता है; अथवा
- (ii) निर्धारित पद्धति से निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख तथा लेखा तैयार करने में विफल रहता है; अथवा
- (iii) निर्धारित अवधि के लिये निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख तथा लेखा रखने में विफल रहता है; अथवा
- (iv) अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र में अभिलेखबद्ध/दर्ज प्रमुख व्यापार स्थल पर निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख रखने तथा/अथवा प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा
- (v) जारी किसी निदेश को अनुपालन करने में विफल रहता है या निर्धारित या अधिसूचित अभिलेख या आयुक्त द्वारा या धारा 58क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इस संबंध में आयुक्त द्वारा नामांकित किसी लेखाकार या लेखाकारों के किसी पैनल या किसी अन्य व्यवसायी या व्यवसायियों के पैनल द्वारा उसे तामील किए गए किसी नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को या पहले प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
- तो व्यक्ति अर्थदंड के रूप में पचास हजार रुपये या कर कमी, यदि कोई हो, का बीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा ।”
- (vi) उप-धारा (19) में आए शब्द “‘चालीस’’ के स्थान पर शब्द “‘बीस’” प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
- (vii) उप-धारा (22) में आए शब्द “‘दस’” के स्थान पर शब्द “‘पच्चीस’” प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
- (viii) उप-धारा (23) के बाद निम्नलिखित सन्निविष्ट की जाएगी ।
- “(24) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाए किन्हीं नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, जिसके लिये अधिनियम के अन्तर्गत अलग से किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गयी है, वह दस हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का उत्तरदायी होगा ।

11. धारा 89 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 89 में--

- (i) उप-धारा (4) के खंड (ज) में शब्द तथा संख्या “‘धारा 59’’ के स्थान पर शब्द तथा संख्याएं “‘धारा 58’”, 58क या 59” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- (ii) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात् :-
- “इस धारा की उप-धारा (1) से (5) में कुछ भी रहते हुए कोई भी व्यक्ति इन उप-धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं करेगा, यदि--
- (क) किसी वर्ष की अवधि के दौरान से सौ रुपये से कम कुल राशि का मामला है; अथवा
- (ख) अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत व्यक्ति ने स्वेच्छा से कर कमी होने को प्रकट किया है ।

12. धारा 102 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (2) का खंड (या) हटाया जाएगा ।

13. नयी धारा 107 को सन्निविष्ट करना.—मूल अधिनियम की धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जायेगी,

अर्थात् :-

“107 क्षमा स्कीम—इस अधिनियम तथा इसकी नियमावली में कुछ भी प्रतिकूल रहते हुए सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 01 अप्रैल, 2013 से पहले समाप्त किसी अवधि से संबंधित “‘अधिनियम’’ के अन्तर्गत कर, ब्याज, अर्थदंड

या कोई अन्य देनदारियों के भुगतान से संबंधित क्षमा स्कीम घोषित कर सकती है और इसमें यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, समय-सीमा के भीतर, कर की दर, ब्याज, अर्थदंड या कोई अन्य देनदारियां जो व्यापारियों की किसी श्रेणी या व्यापारियों की सभी श्रेणियों द्वारा देय हैं।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अस्पष्टता दूर करने के लिये “व्यापार स्थल” और वस्तुओं की परिभाषा संशोधन करने के लिये धारा 2 का संशोधन प्रस्तावित है। धारा 11 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि किसी समय-सीमा के बिना आगामी वर्ष में क्रेडिट शेष अग्रेषित करने के स्थान पर प्रत्येक वर्ष के अन्त में धन वापसी का दावा अनिवार्य रूप से किया जा सके। इसके द्वारा आपत्ति की सुनवाई के लिये पूर्व शर्त के रूप में स्थगन राशि का प्रावधान करके धारा 74(1) के संशोधन 30-9-2011 से किया गया था, और इस प्रकार धारा 35(2) में अनुकूल परिवर्तन प्रस्तावित है। व्यापारी अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज प्रमुख व्यापार स्थल पर लेखा बहिर्या रखता है इसे सुनिश्चित करने के लिये धारा 48 में संशोधन प्रस्तावित है। आयकर अधिनियम में संशोधन की भाँति विशेष लेखा परीक्षा कराने के लिये अधिक मानक जोड़ने के लिये और विशेष लेखा परीक्षा के समय और सर्वेक्षण के दौरान अभिलेख के प्रस्तुतिकरण के लिए व्यापारी द्वारा अनुपालन हेतु भी धारा 58क(1), 86(13) और 89(4) में संशोधन प्रस्तावित है। छानबीन संबंधी उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिये धारा 60(4) और 25(1) में संशोधन प्रस्तावित है। धारा 86(9) के अन्तर्गत शब्द ‘दंड’ सहित ‘अर्थदंड’ हटाने के लिये तथा 12 मासिक विवरणियों की संख्या घटकर 4 तिमाही विवरणियां होने के कारण तिमाही विवरणियां न प्रस्तुत करने के लिये दंड की राशि भी बढ़ाने के लिये धारा 70(5) एवं धारा 102(2)(यग) में संशोधन प्रस्तावित है।

धारा 86 में कुछेक संशोधन विशेषकर उप-धारा (5), (6) तथा (22) में दंड बढ़ाने के संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उसी समय यह प्रस्तावित है कि उप-धारा (19) की दंड जो पहले ट्रांसपोर्टर से जब्त किये गए माल पर देयकर की राशि के बराबर था, यह 18-6-2012 से बढ़ाकर रूपये में 40 पैसे था। फिलहाल अतीत में व्यापारियों ट्रांसपोर्टरों के शोर शराबा करने को ध्यान में रखते हुए घटाकर रूपये में 20 पैसे किया जाना प्रस्तावित है। विभाग ने “कर कमी” संबंधी उप-धारा (1) की अस्पष्टता को दूर कर दिया है जो उक्त उप-धारा में एक व्याख्या देकर स्पष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उप-धारा (2) का द्वितीय उपबंध अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है क्योंकि धारा 86 के अन्तर्गत दंडों की सभी आंकड़े गणितीय गणनाओं पर आधारित हैं और उक्त उपबंध का दुरुपयोग समाप्त करने के लिये और अनावश्यक वाद कार्य रोकने के लिये भी द्वितीय उपबंध को हटाने का प्रस्ताव है।

अधिनियम और नियमावली के ऐसे उपबंधों के उल्लंघन के लिये इस समय किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है, इसके लिये प्रावधान हेतु धारा 86 में एक नयी उप-धारा (24) जोड़ी गई है। ऐसे उन व्यापारियों को अभियोग से राहत देने के लिये धारा 89(7) में संशोधन प्रस्तावित है, जिन्होंने अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत सर्वेक्षण के दौरान अपनी कर कमी की घोषणा की और कर कमी का भुगतान किया है। निकट भविष्य में क्षमा स्कीम लाने के लिये सरकार को सशक्त करने के लिए एक नयी धारा 107 प्रस्तावित है ताकि अधिक से अधिक व्यापारी कर नियमों का पालन करने वाले बन सकें।

प्रस्तावित विधेयक से इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

(शीला दीक्षित)

मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, नई दिल्ली

दिनांक :

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 में किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नए पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है।

प्रत्यायोजन विधान से संबंधी ज्ञापन

मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 में अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 27th August, 2013

No. 21(06)2013/LAS-IV/Leg./5007.—The following is published for general information :—

BILL NO. 06 OF 2013

THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2013

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 27th August, 2013)

3725 ४९/३-२

BILL NO. 06 OF 2013

THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2013**A****BILL****to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004**

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 2.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereinafter referred to as ‘the principal Act’ in Section 2, in sub-section (1)—

(i) for clause (e), the following shall be substituted, namely:

(e) “business premises” includes—

(i) the address of a dealer, registered with the Commissioner;

(ii) any building or place used by a person for the conduct of his business, except for those parts of the building or place used principally as a residence;

(iii) any place from where a dealer carries on business through an agent (by whatever name called), the place of business of such agent; and

a warehouse, godown or such other place where a dealer stores his goods.”

(ii) in clause (m), in sub-clause (ii), after the word ‘movable’ the words “or immovable” shall be inserted.

3. Amendment of section 11.—In the principal Act, in section 11, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

(2) “Where the net tax of a dealer calculated under sub-section (1) of this section amounts to a negative value, the dealer shall—

(a) adjust the said amount in the same tax period against the tax payable by him under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), if any; and

(b) be entitled to carry forward the amount remaining after application under sub-section (2)(a) to next calendar month or tax period, as the case may be, of the same year, or

claim a refund of the amount remaining after application under sub-section (2)(a) at the end of a tax period of the same year and the Commissioner shall deal with the refund claim in the manner described in section 38 and section 39 of this Act.

Explanations—1. Refund can be claimed at the end of a tax period only.

2. Excess tax credit should not be carried forward to the next year.

3. Refund of excess tax credit carried forward from previous years should be claimed in any of the remaining tax periods of year 2013-2014 but not later than the last tax period ending on 31.03.2014.

4. Excess tax credit remaining at the end of a tax period can either be claimed as refund or carried forward to next tax period of the same year.

5. Excess payment made inadvertently shall also be treated as credit in a month or tax period as the case may be.”.

4. Amendment of section 25.—In the principal Act, in section 25, in sub-section (1), after the words “under section 38 of this Act” and before the words “require a person”, the following shall be inserted, namely:—

“or as a condition of de-sealing or release under sub-section (4) of section 60.”.

5. Amendment of section 35.—In the principal Act, in section 35, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

(2) “Where a person has made an objection to an assessment or part of an assessment and has complied with the condition, if any, to entertain such objection in the manner provided in section 74 of this Act, the Commissioner may not enforce the payment of balance amount in dispute under that assessment until the objection is resolved by the Commissioner.”.

6. Amendment of section 48.—In the principal Act, in section 48, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

(i) “Every—

- (a) Dealer;
- (b) person on whom a notice has been served to furnish returns under section 27 of this Act;

shall prepare, maintain and retain sufficient records at the principal place of business as recorded in his certificate of registration to allow the Commissioner to readily ascertain the amount of tax due under this Act, and to explain all transactions, events and other acts engaged in by the person that are relevant for any purpose of this Act. :

Provided that the dealer maintaining computerised books of accounts using a software should be able to readily provide soft and/or hard copy of the records at the principal place of business as recorded in his certificate of registration, as and when required by the Commissioner.

Explanation : The dealer may maintain and retain soft copy of the records as means of compliance with the requirement of this sub-section.”.

7. Amendment of section 58A.—In the principal Act, in section 58A, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

(i) “If the Commissioner, having regard to,—

- (a) the nature and complexity of the business of a dealer; or
- (b) the interest of the revenue; or
- (c) volume of accounts; or
- (d) doubts about the correctness of the accounts; or
- (e) multiplicity of transactions in the accounts; or
- (f) specialised nature of business activity; or
- (g) non-production of all records and accounts; or
- (h) non-filing of audit report under section 49 of this Act; or
- (i) any other reason.

is of the opinion that it is necessary so to do, he may direct the dealer by a notice in writing to get his records including books of accounts, examined and audited by an accountant or a panel of accountants or any other professional or panel of professionals nominated by the Commissioner in this behalf and to furnish a report of such examination and audit in the format that he may specify, duly signed and verified by such accountant or panel of accountants or professional or panel of professionals and setting forth such particulars as may be specified.”.

8. Amendment of section 60.—In the principal Act, in section 60, in sub-section (4), for the word “directed” the word “prescribed” shall be substituted.

9. Amendment of section 70.—In the principal Act, in section 70 of sub-section (5) shall be deleted.

10. Amendment of section 86.—In the principal Act, in section 86,—

(i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

- (1) “In this section “tax deficiency” means the difference between the tax properly payable by the person in accordance with the provisions of this Act and the amount of tax paid by the person in respect of a calendar month.

Explanations I—‘Tax properly payable’ includes the amount of tax assessed under section 32 of the ‘Act’.

2. Due tax paid after the period specified in sub-section (4) of section 3 of the Act, is also a tax deficiency.”.

- (ii) the second proviso of sub-section (2) shall be deleted.
- (iii) in sub-section (5), for the word ‘one’ the word ‘five’ and for the word ‘five’ the word ‘ten’ shall be substituted.
- (iv) in sub-section (6) for the word ‘hundred’ the word ‘thousand’ and for the word ‘five’ the words “twenty five” shall be substituted.
- (v) for sub-section (9), the following shall be substituted, namely :—

(9) “If a person required to furnish a return under Chapter V or to comply with a requirement in a notification issued under section 70 of this Act—

- (a) fails to furnish any return by the due date; or
- (b) fails to furnish with a return any other document that is required to be furnished with the return; or
- (c). being required to revise a return already furnished, fails to furnish the revised return by the due date; or
- (d) fails to comply with a requirement in a notification issued under section 70;

the person shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of five hundred rupees per day from the day immediately following the due date until the failure is rectified :

Provided that the amount of penalty payable under this sub-section shall not exceed fifty thousand rupees.”.

(vi) in sub-section (13), for sub-clause (c), the following shall be substituted, namely :—

(c) “retain prescribed or notified records or accounts:

and the person—

- (i) fails to prepare the prescribed or notified records and accounts; or
- (ii) fails to prepare prescribed or notified records and accounts in the prescribed manner; or
- (iii) fails to retain the prescribed or notified records and accounts for the prescribed period; or
- (iv) fails to retain and/or produce the prescribed or notified records at the principal place of business as recorded in his certificate of registration; or
- (v) fails to comply with a direction issued or fails to produce prescribed or notified records and accounts, or cause them to be produced, on or before the date specified in any notice served on him by the Commissioner or by an accountant or a panel of accountants or any other professional or panel of professionals nominated by the Commissioner in this behalf under sub-section (1) of section 58A;

the person shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of fifty thousand rupees or twenty per cent of the tax deficiency, if any, whichever is greater.”.

(vi) in sub-section (19), for the word ‘ forty’, the word ‘twenty’ shall be substituted.

(vii) In sub-section (22), for the word ‘ten’, the words ‘twenty five’ shall be substituted.

(viii) after sub-section (23), the following shall be inserted, namely :—

“(24) Any person, who contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided under the Act, shall be liable to pay a penalty often thousand rupees.”.

11. Amendment of section 89.—In the principal Act, in section 89,—

- (i) in sub-section (4), in clause (h), for the word and figure "section 59", the word and figures "sections 58, 58A or 59" shall be substituted;
- (ii) for sub-section (7), the following shall be substituted, namely :—
"Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (5) of this section, no person shall be proceeded under these sub-sections, if
 - (a) the total amount involved is less than two hundred rupees during the period of a year; or
 - (b) the person has voluntarily disclosed existence of tax deficiency under sub-section (6) of section 87 of the Act.".

12. Amendment of section 102.—In the principal Act, in section 102, in sub-section (2), clause (zd), shall be deleted.

13. Insertion of new section 107.—In the principal Act, after section 106, the following shall be inserted, namely :—

"107. Amnesty Scheme(s).—Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and Rules thereto, the Government may by notification in the Official Gazette, notify amnesty scheme(s) covering payment of tax, interest, penalty or any other dues under the 'Act', which relate to any period ending before 1st day of April, 2013, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, covering period of limitation, rates of tax, tax, interest, penalty or any other dues payable by a class of dealers or classes of dealers or all dealers.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment in section 2 is proposed to amend the definition of 'place of business' and 'goods' to remove the ambiguity. Amendment in section 11 is proposed so that refund is mandatorily claimed at the end of each year instead of carrying forward the credit balance to next year without any time limit. The section 74(1) was amended w.e.f. 30.09.2011 thereby making provision for stay amount as a pre-condition for hearing the objection and thus a corresponding change in section 35(2) is proposed. Amendment in section 48 is proposed to ensure that the dealer maintains books of account at principal place of business as recorded in his certificate of registration. Amendment in section 58A(1), 86(13) and 89(4) is proposed to add more parameters for conducting special audit in line with the amendment in Income Tax Act and also for compliance by dealer for production of records at the time of special audit and during the course of survey. Amendment in section 60(4) and section 25(1) is proposed for strengthening of provisions relating to security. Amendment in section 70(5) and section 102(2)(zd) is proposed to replace the word 'fine' with the word 'penalty' under section 86(9) and also for increasing the penalty for not filing quarterly returns as the number of returns has been reduced from 12 monthly returns to 4 quarterly returns.

Certain changes in section 86, particularly, in sub-sections (5), (6) and (22) have been proposed to increase the penalty. At the same time, it is proposed that the penalty of sub-section (19) which was earlier equal to the amount of tax payable on seized goods from transporter was increased to 40 paise in a rupee w.e.f. 18.06.2012, is proposed to be decreased to 20 paise in a rupee in view of the hue and cry of the dealers and transporters in the recent past. The department has come across ambiguity in sub-section (1) with regard to 'tax deficiency' which is being clarified by giving an explanation in the said sub-section. Further, the second proviso of sub-section (2) is against the spirit of the Act because all calculations of penalties under section 86 are based on mathematical calculations and to put an end to the misuse of the said proviso and also to avoid unnecessary litigation. It is proposed to delete the second proviso.

A new sub-section (24) is added to section 86 to make provision for penalty for violation of such provisions of the act and rule, for which no penalty exists at present. Amendment in section 89(7) is proposed to give relief from prosecution to such dealers who declare and pay their tax deficiency during the course of survey under section 60 of the Act. A new section 107 is proposed to empower the Government to bring amnesty scheme in near future so that more and more dealers become tax compliant.

The proposed Bill seeks to achieve these objectives.

(SHEILA DIKSHIT)
CHIEF MINISTER/FINANCE MINISTER
• NEW DELHI
DATED :

8725 8/3-3

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2013 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2013 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

सं. 21 (07)/2013/एल ए एस-IV/एल ई जी/5011.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या (07) 2013

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2013

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पुरस्थापित किया गया)

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2013

2013 का विधेयक संख्या 07

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2013

वर्ष 2013-2014 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2013 है ।

2. 531,42,00,000/- रुपयों का वर्ष 2013-2014 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए पांच सौ इक्टीस करोड़ बयालिस लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2013-2014 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

3. **विनियोजन.**—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशि इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवाएं एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधि पर भारित	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	न्याय प्रशासन	पूँजी	30000	30000
4	वित्त	राजस्व	100	100
8	समाज कल्याण	राजस्व	4486400	4486400
9	उद्योग	राजस्व	797500	797500
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	200	200
	जोड़		5314200	5314200

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उप-धारा (1) के साथ पुष्टि धारा 30(1)(क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(श्रीमति शीला दीक्षित)

मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री

दिल्ली :

अगस्त, 2013

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2013 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

No. 21(07)2013/LAS-IV/Leg./5011.—The following is published for general information :—

BILL NO. 07 OF 2013

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2013

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 27th August, 2013)

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2013

BILL NO. 07 OF 2013

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2013

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2013-14.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title.**—This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 3) Act, 2013.

2. **Issue of Rs. 531,42,000 from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014.**—From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees five hundred thirty one crore forty two lac only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2013-2014 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

Demand No.	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Sums Not Exceeding	Total
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
3	Administration of Justice	Capital	30000	..	30000
4	Finance	Revenue	100	..	100
8	Social Welfare	Revenue	4486400	..	4486400
9	Industries	Revenue	797500	..	797500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	200	..	200
Total		5314200	..		5314200

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2013 is introduced in pursuance of sub-section (1) of Section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the additional expenditure charged on the Consolidated Fund and the supplementary grants made by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2013-2014.

(Sheila Dikshit)

Finance Minister/Chief Minister

Delhi,

August, 2013

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 3) Bill, 2013 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

सं. 21 (05)/2013/एल ए एस-IV/एल ई जी./5003.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या (05) 2013

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 27 अगस्त, 2013 को पुरस्थापित किया गया)

2013 का विधेयक संख्या 05

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 में संशोधन के लिये

एक

विधेयक

भारतीय गणराज्य के 64वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) यह अधिनियम दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

2. धारा 3 का संशोधन :—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 की धारा 3 की उप-धारा (4) में,

(क) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(iv) उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व दिल्ली नगर निगम प्रत्येक में से एक सदस्य संबंधित मेयर द्वारा नामित किया जायेगा।”;

(क) खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(vi) निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पदेन।”

(अरविंदर सिंह)

मंत्री, शहरी विकास

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

प्रमुख अधिनियम द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) गठित किया गया था ताकि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के मुद्दों से निपटा जा सके और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (सुधार एवं क्लीयरेंस) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) तथा संबंधित मुद्दों के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) अधिनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान परिषद् द्वारा पास किया गया था और इसे वर्ष 2010 में अधिसूचित किया गया।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) अधिनियम की धारा 3 जो स्थापना के संबंध में है और जिसमें दिल्ली नगर निगम (एससीडी) से दो सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया गया है जो कि मेयर तथा दिल्ली नगर निगम के पदेन आयुक्त द्वारा नामित होते हैं। दिल्ली नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 2011 के अधिनियमन से एकीकृत दिल्ली नगर निगम को तीन शाखाओं में बांटा जो हैं उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व दिल्ली नगर निगम। ये तीनों शाखाओं और तीन नगर निगमों का आपात है जिसने डीयूएसआईबी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को अपरिहार्य बनाया है।

यद्यपि संशोधन अनुवर्ती प्रकृति के हैं, यह महसूस किया गया कि परिवर्तन यथा संभव नाम मात्र के होने चाहिए। तदनुसार बिल में यह प्रस्तावित है कि बोर्ड में समिलित होंगे (i) संबंधित मेयर द्वारा नामित तीनों दिल्ली नगर निगम से एक सदस्य (मेयर द्वारा नामित दो सदस्यों के बदले) तथा (ii) स्थानीय निकायों के निदेशक (दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के बदले)।

इसलिए प्रभावी रूप से, बोर्ड में केवल एक सदस्य शामिल होगा और स्थानीय निकायों के निदेशक तीनों नए निगमों के आयुक्त का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रस्तावित संशोधनों के बिना दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की सम्मिश्रण एवं कार्य पद्धति भ्रमित एवं प्रश्न चिह्न के तहत होगी।

इसलिए यह बिल।

स्थान :

तारीख :

अरविंदर सिंह, मंत्री, शहरी विकास

3725 २५/३-४

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 में प्रस्तावित संशोधन के कारण किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं हैं।

(अरविंदर सिंह)

मंत्री, शहरी विकास

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

विधेयक किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं करता।

(अरविंदर सिंह)

मंत्री, शहरी विकास

पी. एन. मिश्रा, सचिव

No. 21(05)2013/LAS-IV/Leg./5003.—The following is published for general information :—

BILL NO. 05 OF 2013**THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) BILL, 2013**

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 27th August, 2013)

BILL NO. 05 OF 2013**THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) BILL, 2013**

A

BILL

to amend the Delhi Urban Shelter Board Act, 2010.

BE it enacted in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi

In the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette appoint.

2. **Amendment of section 3.**— In the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, section 3, in sub-section (4),

(a) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iv) one Member each from North Municipal Corporation of Delhi, South Municipal Corporation of Delhi and East Municipal Corporation of Delhi to be nominated by the respective Mayor.”;

(b) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:—

“(vi) the Director of Local Bodies, Government of National Capital Territory of Delhi, ex officio.”

(Arvinder Singh)

Minister, Urban Development

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) was constituted by the principal Act in order to deal with the issues of slums in Delhi and implement the provisions of the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956) and related matters. The DUSIB Act was passed by the Legislature of the National Capital Territory of Delhi and notified in the year 2010.

Section 3 of the DUSIB Act, which dealt with the establishment and composition of the Board *inter alia* consisted of two Members from the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to be nominated by the Mayor and Commissioner of MCD, ex officio. With the enactment of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, the erstwhile unified MCD got trifurcated to three namely the North MCD, South MCD and the East MCD. It is this trifurcation and emergence of three Municipal Corporations which has made the proposed amendments in the DUSIB Act indispensable.

Since the amendments are of consequential nature, it was felt that the changes should be as slight as possible. Accordingly, in the Bill, it is proposed that the Board will consist of (i) one Member each from the three MCDs to be nominated by the respective Mayor (in lieu of two Members to be nominated by the Mayor) and (ii) Director of Local Bodies (in lieu of Commissioner of MCD). So effectively, there is addition of only one Member in the Board and the Director of Local Bodies will represent Commissioners of the three new Corporations.

Without the proposed amendments, the composition and functioning of the DUSIB will become confusing and questionable.

Hence this Bill.

(Arvinder Singh)

Minister, Urban Development

Place :

Date :

FINANCIAL MEMORANDUM

There is no additional financial implication due to the proposed amendments in the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010.

(Arvinder Singh)

Minister, Urban Development

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Bill does not envisage delegation of legislative powers to any subordinate authority.

(Arvinder Singh)

Minister, Urban Development

P. N. MISHRA, Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

पत्रांक एफ 60(59)/म.बा.वि.वि./स.नि.म.स.प्र./खंड 4/14638-654.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम 1994 की संख्या 8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार श्रीमती गीता सागर का कार्यकाल दिल्ली महिला आयोग के सदस्य सचिव के रूप में दिनांक 14-7-2013 से 13-7-2014 तक, एक वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 27th August, 2013

No. 60(59)/DWCD/ADWEC/Vol. IV/14638-654.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994), the Government of NCT of Delhi is pleased to extend the tenure of Mrs. Gita Sagar as Member Secretary of the Delhi Commission for Women by one year from 14-7-2013 to 13-7-2014 on the terms and conditions already decided by the Government of NCT of Delhi.

(वित्तीय सहायता अनुभाग)

फा. सं. 41(22) / डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी / एफ.ए.एस. / स्कीम अमेंड / 09-10 / 14624-636.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निराश्रित महिला पेंशन नियमावली, 2010, जैसा कि दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. 41(22) / डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी / एफ.ए.एस. / स्कीम अमेंड / 09-10 / दिनांक 26 नवम्बर, 2010, 31 मार्च, 2011, एवं 01 नवम्बर, 2012, में निम्न संशोधन करते हैं—

1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 18 से 60 वर्ष तक की आयु समूह की निराश्रित महिला पेंशन (संशोधित) नियमावली, 2012 कहा जाएगा।

2. नियम 5(2)(ग) में संशोधन :-

कथित नियमावली के नियम 5(2)(ग) में “महिला पंचायत” के पश्चात् निम्न जोड़ा जाता है :-

“तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा स्वयं घोषना पत्र”

यह संशोधन अधिसूचना के दिनांक से लागू होंगे।

राजीव काले, निदेशक

(Financial Assistance Section)

F. No. 41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/14624-636.—The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the rules in respect of The National Capital Territory of Delhi Pension Scheme to Women in Distress in the age group of 18 to 60 years Rules, 2010, as published in the Delhi Gazette vide Notification F. No. 41(22)/DSW-WCD/FAS/Sch. Amend/09-10/26-11-2010, 31-03-2011 and 01-11-2012 as following namely:—

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These Rules may be called The National Capital Territory of Delhi Pension Scheme to Women in Distress in the age group of 18 to 60 years (Amendment) Rules, 2012.

2. Amendment of Rule 5(2)(C)

In Rule 5(2)(C) of the said Rules, after the words “Mahila Panchayats” these words shall be added, “self declaration by Muslim women in case of divorce”.

This amendment would come into force from the date of notification.

RAJIV KALE, Director

भूमि एवं भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

सं. एफ.10 (6) / 2012 / वैस्ट / भू.व.म. / भू.आ. / 8316.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु नजदीक पीपल वाला चौक, मोहन गाँड़न, उत्तम नगर, गांव हस्तसाल, दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचलित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्त्वाग्रह कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों एवं कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उप-धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू हैं, उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देष हैं कि धारा 5क के उपबंध लागू नहीं होंगे।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	खसरा नं.
हस्तसाल	64 //
	15 / 2(0-5-10)
	65 //
	11 / 2(3- 15)
	12 / 2(3- 15)
	13 / 2(3- 15)
	14 / 2 / 2(0 -6)
कुल क्षेत्र	11-16-10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनाय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 2013

No. F. 10(6)/2012/West/L&B/LA/8316.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of 200 Bedded Hospital Near Pipal Wala Chowk, Mohan Garden, Uttam Nagar, Village Hastsal, Delhi. It is, hereby, notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the Officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of sub-section (1) of Section 17 of the said act are applicable to this land and is further pleased under sub-section (4) of the said section to direct that all the provisions of Section 5A shall not apply.

3725/OS/13-5

SPECIFICATION

Village	Khasra No.
Hastsal	64// 15/2 (0-5-10)
	65// 11/2 (3-15) 12/2 (3-15) 13/2 (3-15) 14/2/2 (0-6)
Total Area	11-16-10

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory Delhi,

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2013

सं. एफ 7(3) / 2008-09 / डीएससीएसटी / एससीपी / 13474.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983 की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित दिल्ली सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम, 2007 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं. एफ. 7(3) / 2008-09 / डीएससीएसटी / एससीपी / 4067 दिनांक 26.6.2010 का अतिक्रमण करते हुए सहर्ष राजकीय समन्वय समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ करते हैं—

1. मंत्री, (अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक के कल्याणार्थी)अध्यक्ष
2. श्री जयकिशन, विधायक (सुल्तानपुर माजरा)सदस्य
3. श्री अरविन्द सिंह, विधायक (देवली)सदस्य
4. श्री चरण सिंह कंडेरा (भूतपूर्व विधायक)सदस्य
- (सामाजिक कार्यकर्ता)
मकान नं.-38, गांव व डाकखाना बाकनेर,
नरेला, दिल्ली-40
5. श्री आर. एन. चंदेलिया, (भूतपूर्व सदस्य
महानगर परिषद) (सामाजिक कार्यकर्ता)
4/2, लाल बहादुर सदन, गोल मार्किट,
नई दिल्ली-110001सदस्य

6. प्रधान सचिव, (राजस्व / क्षेत्रीय आयुक्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54
—सदरस्य
7. सचिव, (शहरी विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
नौवा तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
—सदरस्य
8. आयुक्त,
उत्तरी दिल्ली नगर निगम
चौथी मंजिल, सिविक सेन्टर, मिन्टो रोड,
दिल्ली-110002
—सदरस्य
9. आयुक्त,
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
नौवीं मंजिल, सिविक सेन्टर, मिन्टो रोड,
दिल्ली-110002
—सदरस्य
10. आयुक्त,
पूर्वी दिल्ली नगर निगम
419, उद्योग सदन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
—सदरस्य
11. सचिव,
नई दिल्ली नगर परिषद्
पालिका केन्द्र, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
—सदरस्य
12. कार्यकारी अधिकारी,
दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली कैट-10
—सदरस्य
13. प्रधान सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
अ.जा. / ज.जा. / अ.पि.व. / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बी-ब्लाक, दूसरी मंजिल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002
—सदरस्य—सचिव

सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य कार्यकाल और शर्तें तथा अन्य सम्बन्धित मामले उन नियमों के अनुसार होंगे, जो कि अधिसूचना संख्या एफ. 7(4) / 2002-03 / डीएससीएसटी / एससीपी / (V) / 8829 दिनांक 1.9.2008 गे अधिरूपित किये गये हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश रो तथा उनके नाम पर

3725 Dec/13-6

ललगलरामगांगा, प्रधान सचिव

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 2013

No. F. 7(3)/2008-09/DSCST/SCP/13474.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 13 of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 read with rule 5 of the Delhi Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Rules, 2007 and in supersession of Notification No. F. 7(3)/2008-09/DSCST/SCP/4067 dated 28-06-2010, the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to re-constitute the State Co-ordination Committee consisting of the following members, namely :—

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Minister (Welfare of SCs/STs/OBCs/Min.)
Government of NCT of Delhi | —Chairperson |
| 2. Sh. Jai Kishan , MLA, (Sultanpur Majra),
A-140, Raj Park, Sultanpuri Road,
Delhi-41 | —Member |
| 3. Sh. Arvinder Singh, MLA, (Deoli)
11A, Teen Murti Marg, New Delhi-110011 | —Member |
| 4. Sh. Charan Singh Kandera, (Ex. MLA)
(Social Worker)
H.No. 38, V&PO Bankner, Narela,
Delhi-110040 | —Member
(Non-Official) |
| 5. Sh. R.N.Chandeliya (Ex Member-Metropolitan
Council) (Social Worker),
4/2, Lal Bahadur Sadan, Gole Market,
New Delhi-110001 | —Member
(Non-Official) |
| 6. Principal Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner
Government of NCT of Delhi, 5-Sham Nath Marg,
Delhi-110054 | —Member |
| 7. Secretary (Urban Development)
Government of NCT of Delhi, 9th Level, "C" Wing,
Delhi Secretariat, New Delhi-110002 | —Member |
| 8. Commissioner,
North Delhi Municipal Corporation,
4th Floor, Civic Centre, Minto Road, Delhi-110002 | —Member |
| 9. Commissioner,
South Delhi Municipal Corporation,
9th Floor, Civic Centre, Minto Road, Delhi-110002 | —Member |
| 10. Commissioner,
East Delhi Municipal Corporation,
419, Udyog Sadan, Patparganj, Delhi-110092 | —Member |
| 11. Secretary,
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi-01 | —Member |
| 12. Executive Officer,
Delhi Cantonment Board,
Delhi Cantt.-110010 | —Member |

13. Pr. Secretary (SC/ST /OBC/Min.)
Government of NCT of Delhi, "B" Block,
1Ind Floor, Vikas Bhawan,
New Delhi-110002.
- Member-Secretary

The powers and functions, the terms and conditions of the members and other matters connected therewith shall be in accordance with the said Rules notified vide Notification No. F. 7(4)/2002-03/DSCST/SCP (V)/8829 dated 01-09-2008.

By Order and in the Name
of the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

LALMALSAWMA, Pr. Secy.